



दवियांगजन और न्याय प्रणाली तक आसान पहुँच

प्रलिस के लयि

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत सदिधांत, दवियांगजन अधकार अधनियम 2016

मेन्स के लयि

भारत में दवियांगजनों की स्थिति और उनसे संबंधित समस्याएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दवियांग व्यक्तियों के लयि सामाजिक न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अपनी तरह के पहले दशा-नरिदेश जारी कयि हैं, जसिसे ऐसे व्यक्तियों के लयि न्याय प्रणाली का उपयोग करना काफी आसान हो जाएगा।

प्रमुख बदि

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दशा नरिदेशों में 10 सदिधांतों के समूह की एक रूपरेखा तथा उसके कार्यान्वयन के लयि आवश्यक वभिन्न कदमों का उल्लेख कयि गया है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लेखित 10 सदिधांत हैं-
 - सदिधांत 1: दवियांग व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता है और इसलयि दवियांगता के आधार पर कसिी को भी न्याय तक पहुँचने से वंचित नहीं कयि जा सकता है।
 - सदिधांत 2: दवियांग व्यक्तियों के लयि भेदभाव के बनिा न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लयि सुवधाओं एवं सेवाओं का सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना अनविर्य है।
 - सदिधांत 3: दवियांग बच्चों समेत सभी दवियांग व्यक्तियों को उचित 'प्रसीजरल एकोमोडेशन' (Procedural Accommodation) का अधकार है।
 - 'प्रसीजरल एकोमोडेशन' का अभिप्राय ऐसे उपायों से होता है, जो कसिी दवियांग व्यक्ति अथवा संवेदनशील व्यक्तिको कानूनी प्रक्रया में मदद करते हैं, जैसे- दवियांग व्यक्तिके साथ कसिी अन्य सहायक व्यक्तिको सुनवाई में हसिसे लेने की अनुमति देना, दवियांग व्यक्तिको वीडयो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में हसिसा लेने की छूट देना और उनके लयि अधिक अनौपचारिक वातावरण का नरिमाण करना।
 - सदिधांत 4: दवियांग व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों की तरह कानूनी नोटसि और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधकार है।
 - सदिधांत 5: अन्य व्यक्तियों की तरह दवियांग व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में मान्यता प्राप्त सभी मौलिक और प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं।
 - सदिधांत 6: दवियांगजनों को मुफ्त और मतिव्ययी कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधकार है।
 - सदिधांत 7: अन्य व्यक्तियों की तरह दवियांग व्यक्तियों को न्याय प्रणाली के प्रशासन में समान आधार पर भाग लेने का अधकार है।
 - सदिधांत 8: दवियांग व्यक्तियों के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के मामलों की शकियात करने तथा इस संबंध में कानूनी कार्यावाही शुरू करने का अधकार है।
 - सदिधांत 9: दवियांग व्यक्तियों के लयि न्याय तक पहुँच का समर्थन करने में प्रभावी एवं मज़बूत नगरानी तंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिाते हैं।
 - सदिधांत 10: न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दवियांग व्यक्तियों के अधिकारों खासतौर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित कयि जाना चाहयि।

संयुक्त राष्ट्र की परभाषा में दवियांग व्यक्ति

- 21वीं सदी में मानवाधिकारों के प्रमुख साधन के रूप में पहचाने जाने वाले 'वकिलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) में दवियांग व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परभाषित किया गया है, जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष हैं जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं।
- सामान्य अर्थों में दवियांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है।

दवियांग व्यक्त-संबंधित समस्याएँ

- वशिषज्जों का मानना है कि देश में दवियांगता की ऐसी कई श्रेणी जैसे चोटों, दुर्घटनाओं और कुपोषण आदि हैं, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, कति देश का स्वास्थ्य क्षेत्र खासतौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र इस प्रकार की दवियांगता को भी रोकने में असफल रहा है।
- इसके अलावा देश में कई संवेदनशील वर्गों के लिये उचित स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और उपकरणों तक मतिव्ययी पहुँच का भी अभाव है।
- भारत की शिक्षा प्रणाली में समावेशन का अभाव है, नियमित विद्यालयों में आज भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा एक दवियांग बच्चे के लिये प्रवेश लेना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- दवियांग विद्यार्थियों के लिये वशिषित विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और वशिषित शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।
- कई उच्च शिक्षण संस्थानों में दवियांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है।
- यद्यपि अधिकांश दवियांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम हैं, कति इसके बावजूद भी दवियांग वयस्कों में रोजगार की दर काफी कम है। वदिति हो कि निजी क्षेत्र में दवियांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति और भी खराब है।
- देश में अधिकांश इमारतें और परिवहन सेवाएँ दवियांग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु अनुकूल नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- परिवार और समाज का नकारात्मक व्यवहार प्रायः दवियांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या कार्यबल में सक्रिय भूमिका अदा करने से रोकता है।
- दवियांगजनों के अपने रोजमर्रा के जीवन में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर मानसिक रूप से अक्षम लोग जीवन के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं।

//

भारत में दवियांग

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकत्रित किये गए आँकड़ों के अनुसार, भारत में सभी आयु वर्गों में 2.4 प्रतिशत पुरुष और 2 प्रतिशत महिलाएँ दवियांगता से परभावित हैं। इसमें मानसिक तथा बौद्धिक दवियांगता और बोलने, सुनने तथा देखने संबंधी अक्षमता शामिल है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल 121 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति 'अक्षम' अथवा दवियांग हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं।

- जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दवियांग वयक्तयिों में से 1.5 करोड़ दवियांग पुरुष हैं और 1.18 करोड़ दवियांग महिलाएँ हैं ।
- देश की अधकिांश दवियांग आबादी (69 परतशित) ग्रामीण भारत में नविस करती है ।

दवियांग वयक्तयिों संबन्धी कानून- दवियांगजन अधकिार अधनियिम, 2016

- दवियांगजन अधकिार अधनियिम, 2016 ने वर्ष 1995 के दवियांगजन अधकिार अधनियिम का स्थान लयिा था ।
- इस अधनियिम में दवियांगता को एक वकिसति और गतशील अवधारणा के आधार पर परभिषति कयिा गया है और दवियांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दयिा गया है । इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधकिार दयिा गया है कविह दवियांगता के प्रकारों को और अधकि बढ़ा सकती है ।
- अधनियिम के तहत बेंचमार्क वकिलांगता (Benchmark-Disability) से पीड़ति 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लयि नःशुल्क शकिषा की वयवस्था की गई है ।
 - बेंचमार्क वकिलांगता से अभपिराय उन लोगों से है जो कम-से-कम 40 परतशित वकिलांगता से प्रभावति हैं ।
- अधनियिम के प्रावधानों के तहत दवियांग वयक्तयिों को वत्तितीय सहायता प्रदान करने के लयि एक अलग राष्ट्रीय तथा राज्य कोष बनाया जायगा ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-un-guidelines-on-access-to-social-justice-for-people-with-disabilities>